गरीबी के भंवर में धकेलता इलाज का खर्च



जनवरी 2025 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं व इलाज के खर्च को लेकर दो प्रमुख रुझान सामने आए हैं। पहला देश में रोगग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ी है। और दूसरा लोगों की निर्भरता अब भी महंगे निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर बनी हुई है।

निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दबदबा -

- एनएसएस सर्वेक्षण के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अस्पताल में भर्ती हुए इलाज के मामले 65.4% तथा शहरी क्षेत्रों में 74.8% रहे।
- वहीं ओडिशा में 60%, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 50%, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य सेवा काम आई। कई अन्य राज्यों में यह अनुपात एक-चौथाई से कम रहा।

  इस अंतर का कारण अस्पताल तक पहुँच, इलाज के लिए इंतजार का समय तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता है।

इलाज के खर्च में भारी अंतर -

अस्पताल में बिना भर्ती हुए बीमारी पर अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च 304 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 357 रुपये शहरी क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में था। निजी स्वास्थ्य केंद्रों में यही खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1541 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1343 रुपये रहा।

अस्पताल में भर्ती होने पर बढ़ती लागत -

- प्रसव को छोड़कर अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 31,484 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 38,688 रुपये था। निजी अस्पतालों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 47,710 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 54,999 रुपये था।
- सरकारी अस्पतालों में यही खर्च क्रमशः 6905 तथा 6032 रुपये था।

ऐसे स्वास्थ्य खर्चों के कारण कई बार गरीब अपनी जरूरतों में कटौती करता है। कई बार उसे अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ती है। इसे इलाज के खर्च के कारण गरीबी के जाल में फँसना कहा जाता है। बिहार व उ.प्र. में यह अधिक होता है।

स्वास्थ्य बीमा पर्याप्त नहीं -

- स्वास्थ्य बीमा कार्ड इलाज के समय वित्तीय सुरक्षा का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। कई बार स्वास्थ्य केंद्र का पास में न होना, जरूरी दवाओं, जाँच-सुविधाओं तथा डॉक्टर और इलाज की गुणवत्ता का सुनिश्चित न होना होता है।
- स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ने के बावजूद स्वास्थ्य पर लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्च बढ़ा है। इसका एक कारण सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की रोजमर्रा की कार्यक्षमता की धीमी रफ्तार भी है।

आगे की राह -

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर स्तर पर मजबूत किया जाए।
- आरोग्य मंदिरों से लेकर जिला अस्पतालों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित हो।
- सार्वजनिक बीमा स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसी परिवार को इलाज के लिए अपनी आर्थिक सुरक्षा दाँव पर न लगानी पड़े।

*****